in corrugated Fibre-board Cartons. The use of these Cartons has already been initiated by Himachal Pradesh Horticultural Produce Marketing and Processing Corporation, Simla, Jammu and Kashmir and Uttar Pradesh Directorate of Horticulture on a limited scale. However, further promotion of these cartons could not be enhanced due to their higher price as compared to conventional timber boxes.

### मिल-मालिकों द्वारा गन्ना उत्पादकों का शोषण

9. श्री निहाल सिंह : क्या खाद्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गन्ना उत्पादक राज्यों में निजी क्शरों के मालिक सरकारी दर से आधी दर पर किसानों से गन्ना खरीद रहे हैं और किसानों को भारी हानि हो रही है ; और

(ख) क्या सरकार का विचार इस बात को सुनिश्चित करने का है कि निजी क्शरों के मालिक भी सरकारी दरों पर अदायगियां करें ?

खाद्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री भगवत झा आजाद ) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार केवल निर्यात पात्र चीनी मिलों द्वारा देय गन्ने के सांविधिक न्यूनतम मूल्य निर्धारित करती है। प्राइवेट क्शर असंगठित क्षेत्र में आते हैं और उनके लिए ये मूल्य देना अनिवार्य नहीं है ।

गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 के खण्ड 4 के अधीन केन्द्रीय सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार की अनुमति से राज्य सरकार खण्डसारी चीनी के उत्पादकों द्वारा अदा किए जाने वाले न्यूनतम मूल्य निर्धारित कर सकती है । उद्योग के स्वरूप को दृष्टि में रखते हुए, जैसाकि
किया गया है, केन्द्रीय सरकार अपनी शक्तियों का प्रयोग केवल राज्य सरकार की सिफारिश पर ही करती है । वर्तमान मौसम के दौरान क्शरों के लिए न्यूनतम मूल्य केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति प्राप्त करने के बाद केवल आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा ही निर्धारित किए गए हैं । किसी अन्य राज्य के लिए इस प्रकार के मूल्य निर्धारित करने के बारे में कोई भी प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

### Announcement of Support Price Before Next Kharif Season

10. SHRI ANANTHA RAMULU MALLU:

SHRI H. N. BAHUGUNA:

Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether there is any proposal under consideration of Government to declare the agricultural prices much before the commencement of the next Kharif season so that the farmers could plan their sowing programme in advance;

(b) whether any study has been made by the Institute of Economic Growth and suggested some measures to the Union Government for the revival of the Indian economy; and

(c) if so, the details regarding the check on the pricing policy of the public sector by comparing it with international and domestic market prices?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI ARIF MOHAMMAD KHAN): (a) No such proposal is under the consideration of the Government. The general policy of the government, however, is that procurement or support prices for different crops are announced as early as possible during the season.